भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 574
जिसका उत्तर दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 को दिया जाना है

राष्ट्रीय विद्युत सचलता मिशन योजना, 2020

574. श्री अनिल देसाई :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि माननीय प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय विद्युत सचलता मिशन योजना, 2020 के अंतर्गत लोगों से पेट्रोलियम उत्पादों, बिजली तथा हाइब्रिड ईंधन चालित वाहनों के उपयोग में कमी लाने का आहवान किया है;

(ख) यदि हां, तो योजना का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सार्वजनिक वाहनों के उपयोग पर उनके बल को देखते हुए क्या सरकार लोगों को निजी वाहन का इस्तेमाल कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन को अपनाने हेतु मोटर वाहनों के निर्माण पर कुछ पाबंदी लगाने का विचार करेगी; और

(ग) क्या सरकार निजी वाहनों की गैर अनुपातिक संख्या तथा भारतीय सड़कों की अपर्याप्त चौड़ाई को देखते हुए सुचारु परिवहन व्यवस्था हेतु कारों की बिक्री पर कोई पाबंदी लगाने पर विचार करेगी?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रफुल पटेल)

(क) माननीय प्रधान मंत्री ने दिनांक 09.01.2013 को एनईएमएमपी - 2020 के शुभारंभ के दौरान परिवहन सेक्टर की तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए सभी संभव प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया था और कहा था कि इसका एक उपाय जिससे इसे प्राप्त किया जा सकता है, वह हाइब्रिड वाहनों सहित विद्युत वाहन प्रौद्योगिकियों की पूर्ण श्रृंखला को तेजी से अपनाना है क्योंकि ये प्रौद्योगिकियां कुशल और स्वच्छ हैं।

(ख) नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 का उददेश्य स्वदेशी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के साथ, वर्ष 2020 तक, धीरे-धीरे भारत में विद्युत और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने के लिए बहुत से अंत:क्षेपों के माध्यम से सुविधाएं देना है। सरकार कई नगरों में मैट्रो रेल सेवाओं के विस्तार जेएनएनआरयूएम के तहत बसों हेतु वित्तपोषण आदि जैसी योजनाओं को लागू करके सार्वजनिक परिवहन को भी सुविधाजनक बना रही है।

(ग) देश में कारों की और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।